अमर उजाला

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

युवाओं का यह कर्तव्य है कि वे भ्रष्टाचार को चुनौती दें...

...कर्ट कोबिन, अमेरिकी गायक

आखिर ऐसा क्या हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय को लाखों परिवारों को जंगलों से बाहर निकालने का सख्त आदेश पारित करना पड़ा है, जिस पर अमल हुआ, तो बड़ी संख्या में लोगों को वनभूमि से बाहर होना पड़ेगा?

जंगल पर अधिकार

देश के सोलह राज्यों के लगभग 11.8 लाख परिवारों की वनभूमि पर दावेदारी को खारिज करने के साथ आगामी जुलाई से पहले इन जंगलों को खाली करवा लेने का सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आदिवासियों और वनवासियों के लिए झटका तो है ही, यह वंचितों के हक की लड़ाई के मामले में हमारे दयनीय रिकॉर्ड का एक और उदाहरण भी है। करीब अस्सी साल बाद 2006 में आदिवासियों और वनवासियों को वनाधिकार अधिनियम के तौर पर ऐसा कानून मिला था, जो उन्हें जंगलों में रहने का हक प्रदान करता था। उस कानून को स्वाभाविक ही संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची का विस्तार माना गया था, जिनमें आदिवासियों के हित सुरक्षित हैं। इस बीच आखिर ऐसा क्या हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय को लाखों परिवारों को वनभूमि से बाहर निकालने का सख्त आदेश पारित करना पड़ा है, जिस पर अमल हुआ, तो बड़ी संख्या में लोगों को वनभूमि से बाहर होना पड़ेगा? दरअसल उस कानून के पारित होने के साथ ही उन तत्वों ने उसका विरोध शुरू कर दिया था, जिनके हित उससे प्रभावित होने वाले थे। इनमें वनाधिकारियों से लेकर वन्यजीवन संरक्षण से जुड़े समूह भी थे। वनभूमि पर ताकतवर लोगों के गैरकानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई के बजाय ताकतवर लोगों और लॉबियों ने वनाधिकार अधिनियम को कमजोर करना शुरू किया। जिन अधिकारियों पर वनाधिकार कानून को लागू करने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने जान-बूझकर इसका क्रियान्वयन मुश्किल कर दिया। जिस आदिवासी मामलों के मंत्रालय को वनाधिकार अधिनियम लागू कराने की नोडल एजेंसी बनाया गया था, उसकी सक्रियता भी इस दिशा में कुछ खास नहीं रही। तिस पर निहित तत्वों ने वनाधिकार अधिनियम के खिलाफ अदालत में याचिकाएं डालीं कि इससे तो जंगल ही खत्म हो जाएंगे। यह गलत सोच है कि वनभूमि में रहने वाले जंगल का विनाश करते हैं। बल्कि देश-दुनिया का अनुभव

बताता है कि वे ही जंगल की रक्षा करते हैं। हमारे यहां नक्सल समस्या की एक वजह जंगलों के बारे में हमारा यह अज्ञान ही है। केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकारों द्वारा वनभूमियों से निकाले जाने वाले लोगों का आंकड़ा मिलने पर वह कदम उठाएगी। उसे जल्दी ही इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि इस मामले में ढिलाई से उन आदिवासियों को व्यापक विस्थापन का सामना करना पड़ेगा, जिनके पुनर्वास के मामले में हमारा रिकॉर्ड पहले ही बहुत खराब है।

कश्मीरी युवाओं को कैसे जोड़ें

हमें अंतरराष्ट्रीय ख्याति के एक गैर-राजनीतिक, गैर-नौकरशाह व्यक्ति की आवश्यकता है, जो न तो बंटवारे की बात करता हो और न ही वह राज्य के गलत शासन से जुड़ा हो, लेकिन जिसे युवा सुन सकते हों और भरोसा कर सकते हों।

पुलवामा में हुए आत्मघाती बम धमाके से, जिसमें सीआरपीएफ के चालीस जवान मारे गए, देश भर में व्यापक गुस्सा और आक्रोश है। पाकिस्तान को सबक सिखाने का आह्वान चरम पर पहुंच गया है। जैश-ए-मोहम्मद द्वारा जिम्मेदारी लेने के बावजूद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इस हमले से किसी तरह का संबंध न होने का दावा किया है। भारत से उनका कार्रवाई करने योग्य सुबूत मांगना हास्यास्पद है। क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान को आतंकवादी हमले की निंदा और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करनी चाहिए थी। जाहिर है, वह अपने आकाओं की नाराजगी का जोखिम मोल नहीं लेना चाहते थे।

सुरेंद्र कुमार
पूर्व राजदूत

प्रधानमंत्री मोदी के बयान से जनता की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके 'भीतर भी आग जल रही है' और यह चेतावनी कि 'बातचीत का समय खत्म हो गया है'। वह कार्रवाई के लिए उच्च स्तर पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। पाकिस्तान से सबसे पसंदीदा मुल्क का दर्जा वापस लेना और पाकिस्तानी उत्पादों पर 200 फीसदी शुल्क लगाना उसी दिशा में उठाया गया कदम है। लेकिन अलगाववादी नेताओं से सुरक्षा वापस लेने से उनकी गतिविधियों पर नजर नहीं रखी जा सकेगी। वैश्विक समुदाय आतंकवाद और उसका समर्थन करने वालों के खिलाफ एकजुट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी की बार-बार अपील के बावजूद आज तक आतंकवाद की परिभाषा पर सर्वसहमति नहीं बन सकी है!

एक सफल ऑपरेशन से प्रधानमंत्री की छवि चमकेगी और भाजपा की चुनावी संभावना बढ़ेगी। पर क्या भारत की दंडात्मक कार्रवाई और पाकिस्तान के प्रतिकार से दो परमाणु संपन्न मुल्कों के बीच शत्रुता नहीं बढ़ेगी, जो नियंत्रण से बाहर जा सकती है? दूसरी तरफ, ऐसे उत्तेजक माहौल के बाद क्या सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं कर पाना बर्दाश्त कर सकती है? और इसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री पर ही

आएगी। यह मोदी के लिए मुश्किल फैसला हो सकता है।

इस समय पाकिस्तान के अलग-थलग पड़ने का दावा एक मिथक है। कई अरब देशों द्वारा पाकिस्तान को समर्थन करने का सबसे मजबूत कारक इस्लाम है। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में वहां अरबों डॉलर निवेश करने का वायदा किया है। जब भाई (पाकिस्तान) और प्रिय मित्र (भारत) के बीच चुनने का मौका आएगा, तो वे हमेशा पाकिस्तान को चुनेंगे! चीन मजबूती के साथ पाकिस्तान के पीछे खड़ा है।

ट्रंप द्वारा पाकिस्तान की कड़ी निंदा के बावजूद अमेरिका अपनी सीमाओं से वाकिफ है। पाकिस्तान की मदद के बिना न तो तालिबान के साथ उसकी सार्थक बातचीत हो सकती है और न ही वह आसानी से अफगानिस्तान से बाहर निकल सकता है। रूस के हित भी पूरी तरह से हमारे साथ नहीं हैं। बहरहाल, हमें लगातार अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ अपने आर्थिक और सामरिक संबंधों का लाभ उठाते रहना चाहिए, ताकि भारत में आतंकवाद का निर्यात न करने का पाकिस्तान पर दबाव पड़े। पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल अपनी राज्य नीति के अभिन्न हिस्से के रूप में करता है। लेकिन यह दावा करना, कि घाटी में आतंकवाद का कोई आंतरिक आयाम नहीं है, झूठ है।

वक्त आ गया है कि हम आत्मनिरीक्षण करें। तीन दशकों से ज्यादा समय से घाटी में सेना तैनात है, ज्यादातर समय वहां अफ्स्पा लागू रहा। राज्य पुलिस अक्सर तलाशी अभियान चलाती है। पत्थरबाजों को खदेड़ने के लिए जिंदा पैलेट दागे जाते हैं। इन उपायों और कई आर्थिक पहल की घोषणाओं के बावजूद घाटी के कितने युवा केंद्र सरकार के साथ हैं? सच यह है कि कश्मीर घाटी के युवा व्यापक रूप से अलग-थलग पड़ गए हैं। जब तक हम इसे ईमानदारी और लगन से रोकने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम इनका दिल नहीं जीत सकते। लीक से हटकर कुछ अलग कदम उठाने से इस बिगड़ती स्थिति को रोका जा सकता है-

एक, कश्मीरी नेताओं की पुरानी पीढ़ी अपनी साख खो चुकी है। नई पीढ़ी केंद्र पर भरोसा नहीं करती। हमें अंतरराष्ट्रीय ख्याति के एक गैर-राजनीतिक, गैर-नौकरशाह व्यक्ति की आवश्यकता है, जो न तो बंटवारे की बात करता हो और न ही वह राज्य के गलत शासन से जुड़ा हो, लेकिन जिसे युवा सुन सकते हों और भरोसा कर सकते हों। वैसे एकमात्र व्यक्ति हैं दलाई लामा, जिनके पास नैतिक अधिकार है, बेदाग कद है और जिनके दिल में अपार करुणा है। लेकिन क्या वह इसके लिए सहमत होंगे?

दो, जिस तरह दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी शासन के पतन के बाद शांति और सुलह आयोग की स्थापना की गई थी, उसी तरह के आयोग की यहां स्थापना करनी चाहिए, जो जम्मू-कश्मीर के सभी पीड़ित नागरिकों को शिकायत दर्ज कराने के लिए आमंत्रित करे। इससे कड़वाहट कम हो सकती है और सुलह की एक छोटी-सी खिड़की खुल सकती है।

तीन, वैसे लोगों की पहचान करनी चाहिए, जिन्होंने बिना सख्त रुख अपनाए विरोध करने वाले युवाओं को गिरफ्तारी की धमकी के बिना खुली बहस के लिए आगे आने के लिए कहा और उन्हें मजबूत तर्कों से निहत्था कर दिया कि न तो कश्मीर स्वतंत्र होगा और न ही पाकिस्तान को गले लगाना एक व्यावहारिक विकल्प है। कश्मीर का बंटवारा तो कभी होगा नहीं और दूसरा विकल्प उन्हें मुहाजिर बना देगा, जिसके कारण पाकिस्तान में उन्हें दोयम दर्जे की नागरिकता मिलेगी। ऐसा करने पर सच को स्वीकार करने के लिए बड़ी संख्या में युवाओं के आने की संभावना है, जो भारत में बने रहने को सबसे अच्छा विकल्प मानेंगे। चार, शाह फैसल जैसे स्वच्छ छवि के कश्मीरी युवा, जिन्होंने कुछ साल पहले सिविल सर्विस परीक्षा में टॉप किया था और बाद में इस्तीफा दे दिया, को जम्मू-कश्मीर के ब्रांड एंबेसेडर के रूप में चुना जाना चाहिए। घाटी के युवाओं का दमन और वहां की जनसांख्यिकी में बदलाव से स्थितियां और बिगड़ेंगी।

पांच, कश्मीरी युवाओं का कट्टरपंथी होना एक सच्चाई है। लेकिन उन्हें इससे रोकने के लिए हमने क्या किया है? हम जेहादी रंगरूटों को उनके अपने ही खेल में क्यों नहीं हरा सकते? क्या हमारे पास जेहादियों का मुकाबला करने के लिए उससे ज्यादा मजबूत उपाय है? अगर हमारे पास ऐसा उपाय है, तो यह अजूबा है!

संस्कृति सभ्यता से ज्यादा लचीली होती है

अपनी कहानी

>> संजय सुब्रमण्यम

इतिहास और मान्यताओं के बीच हमेशा एक तनाव चलता रहता है, लेकिन हाल-फिलहाल में भारत में पेशेवर इतिहासकारों के काम को जिस तरह नकारा जा रहा है, वह दुखद है। इतिहास को आज की राजनीति के मुताबिक कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।

मेरा जन्म इक्कीस मई, 1961 को हुआ था। मेरे पिता देशे के जाने-माने सामरिक विशेषज्ञ रहे हैं। पूर्व विदेश सचिव एस जयशंकर मेरे भाई हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक व परास्नातक करने के बाद 1987 में मैंने डेल्ही स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पीएच.डी. पूरी की। मेरे पीएच.डी. शोध का विषय था-*ट्रेड ऐंड द रीजनल इकोनॉमी ऑफ साउथ इंडिया, 1550-1650*। इस तरह शुरू से ही मेरी दिलचस्पी अर्थव्यवस्था के ऐतिहासिक आयामों को समझने में रही है।

फ्रांस से कैलिफोर्निया तक

मैंने लंबे समय तक डेल्ही स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ही आर्थिक इतिहास और तुलनात्मक आर्थिक विकास पढ़ाया है। फिर 1995 में मैं फ्रांस चला गया, जहां मुझे पेरिस के प्रतिष्ठित स्कूल फॉर एडवांस्ड स्टडीज इन द सोशल साइंसेस में पढ़ाने का अवसर मिला। मैंने वहां मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ाया। कुछ साल वहां टिकने के बाद 2002 में मैं ऑक्सफोर्ड चला गया। दरअसल वहां भारतीय इतिहास और संस्कृति की पढ़ाई शुरू की गई थी और ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़ना मेरे लिए फख्र की बात था। मगर दो साल में ही मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिलिस यानी यूसीएलए में पढ़ाने चला गया, जहां साल 2005 में मैं भारत व दक्षिण एशिया के नए अध्ययन केंद्र का संस्थापक निदेशक बना।

सभ्यता से बेहतर संस्कृति

एक लंबे अकादमिक सफर के दौरान एशियाई, यूरोपीय और उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के लोगों के बीच अंतर-सांस्कृतिक संपर्क पर मेरा काम जारी रहा। मैंने पिछली कई सदियों पर काम किया है तथा सभ्यता और विकास के अलग-अलग पैमानों को समझने की कोशिश की है। लेकिन मैं मानता हूं कि सभ्यता अपने आप में एक समस्या हो सकती है। इसके तहत कुछ लोगों को दूसरों पर राज करने का हक मिल जाता है, क्योंकि वे अपने को स्वयंभू सभ्य मानने लगते हैं। यूरोप या पश्चिमी दुनिया को लें और उसकी तुलना में इस्लामी दुनिया, भारत और चीन को रखें। आप पाएंगे कि दुनिया के इन भू-भागों में सभ्यता के अलग-अलग मापदंड हैं। मुझे संस्कृति शब्द ज्यादा भाता है, जिसमें बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है। वहीं, सभ्यता दूसरों को नीचा दिखाने का एक हथियार मात्र है।

इतिहास के प्रति दृष्टिकोण

कई देशों में इतिहास को लेकर काफी आलोचनात्मक रवैया अपनाया गया है। छात्रों को इतिहास को इसी नजरिये से देखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। इतिहास किसी के लिए विश्वास, आस्था या तथ्य का विषय हो सकता है। मगर मेरे जैसे पेशेवर इतिहासकार के लिए यह क्षेत्र इन धार्मिक दृष्टिकोणों से हटकर है। इतिहास और मान्यताओं के बीच हमेशा एक तनाव चलता रहता है, लेकिन हाल-फिलहाल में भारत में पेशेवर इतिहासकारों के काम को जिस तरह नकारा जा रहा है, वह दुखद है। इतिहास को आज की राजनीति के मुताबिक कभी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। जैसा कि टीपू सुल्तान या औरंगजेब को लेकर आज के राजनीतिज्ञ करते हैं।

-इस्राइल के प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय डेन डेविड पुरस्कार के लिए चुने गए मशहूर इतिहासकार संजय सुब्रमण्यम के विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

सूत्र

>> तदाशी यनाई

पैतृक व्यवसाय को अपनाकर बनाई राह

विश्वविद्यालय की पढ़ाई के बाद रोजगार की तलाश मेरे लिए आखिरी चीज थी। मैं काम का भूखा नहीं था। मुझे काम करने के लिए प्रेरित नहीं किया गया था। मेरे पिता ने मुझे रोजगार तलाशने के लिए कहा, तो मैंने अनिच्छापूर्वक एक दूकान जस्को पर नौकरी ढूंढ़ ली। दुकान पर मैंने बर्तनों के साथ-साथ कई तरह के उत्पाद बेचे। लेकिन फ्लोर मैनेजर हमेशा मुझसे शिकायत करता था कि मैं टाई क्यों नहीं बांधता हूं और काम पर आते वक्त जीन्स क्यों पहनता हूं। लेकिन मेरा जैसा काम था, उसे मैं टाई बांधकर कैसे कर सकता था! फ्लोर मैनेजर ने मुझे कहा कि ग्राहकों के सामने ठीक से कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन वह मुझे पसंद नहीं था। खैर कुछ महीनों बाद मैंने वह नौकरी छोड़ दी, हालांकि वह कंपनी अच्छी थी। उसके बाद मैं अपने पिता के व्यवसाय से जुड़ा। पहली मंजिल पर व्यवसाय का काम चलता था और दूसरी मंजिल पर हमारा परिवार था। वहीं मेरी परवरिश हुई थी और चूंकि मैं कहीं आता-जाता नहीं था, इसलिए पिता ने मुझे अपने व्यवसाय में मदद करने के लिए कहा। विडंबना देखिए, कि उसमें मुझे मजा आने लगा। हालांकि उससे पहले मुझे उससे घृणा आती थी। मेरे पिता सूट और टाई बेचने का व्यवसाय करते थे, इसलिए मैं शुरू में उसे पसंद नहीं करता था। लेकिन बाद में मैंने महसूस किया कि यह बेहद दिलचस्प है। मैंने महसूस किया कि किसी भी चीज के प्रति पूर्वधारणा बनाना ठीक नहीं है, बल्कि कोई राय बनाने से पहले उसे आजमाना चाहिए। यह पहली सीख थी, जो मुझे अपने अनुभव से मिली। और उसके बाद मैंने कई व्यवसायों में हाथ आजमाया और सफल रहा। मैंने 'फास्ट रिटेलिंग' की स्थापना की, जिसकी सहायक कंपनी यूनीक्लो है। मैंने शुरुआती चार वर्षों में जापान में 300 स्टोर खोले। जब हम जापान में सफल रहे, तो फिर लंदन में अपने पैर पसारने का मन बनाया। दो से तीन वर्षों में हमारा टर्नओवर एक अरब डॉलर से चार अरब डॉलर हो गया। हमने अपने उत्पाद को सरल, व्यावहारिक और किफायती बनाया। हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमारे उत्पाद हर तरह के लोग पहनें, चाहे वे अरबपति हों, मध्यवर्गीय हों या निम्नवर्गीय हों। जब तक हम जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते, तब तक सफल नहीं हो सकते। सफलता के लिए साहस, लगन, निरंतरता, चुनौती, आत्मविश्वास और सबसे पहले जिज्ञासा का होना जरूरी है।

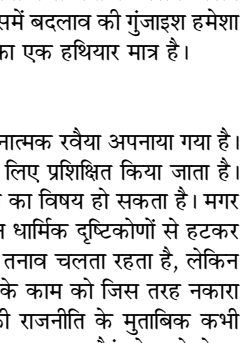

जब तक हम जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते, तब तक सफल नहीं हो सकते।

फैक्ट फाइल

एफएटीएफ

>> एफएटीएफ

1989 में जी-7 के पेरिस में हुए सम्मेलन में एफएटीएफ की स्थापना की गई थी।

द फाइनेंशियल ऐक्शन टॉस्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले की निंदा की है और बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान या तो आतंकी फंडिंग बंद करे या कड़ी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। एफएटीएफ एक अंतरसरकारी संगठन है। 1989 में जी-7 के पेरिस में हुए सम्मेलन में मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) पर अंकुश लगाने के लिए एफएटीएफ की स्थापना की गई थी। नौ सितंबर, 2001 में न्यूयॉर्क स्थित ट्विन टावर पर हुए अल कायदा के आतंकी हमले के बाद इसके दायरे में आतंकी फंडिंग को भी शामिल कर लिया गया। एफएटीएफ एक तरह से नीति नियंता संस्था है, जिस पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग को रोकने के उपाय करने और दिशा-निर्देश जारी करने की जिम्मेदारी है। स्थापना के समय एफएटीएफ के 16 सदस्य थे, जो 2016 में बढ़कर 37 हो गए। अपनी स्थापना के पहले वर्ष में इसने मनी लॉन्ड्रिंग पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिए चालीस सिफारिशें की थीं। 2003 में इसके मानकों में बदलाव किया गया, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के बदलते तरीकों और नई तकनीक से मुकाबला किया जा सके। इसके अलावा 2001 में इसने आतंकी फंडिंग को लेकर अलग से आठ विशेष सिफारिशें भी की थीं। पाकिस्तान को एफएटीएफ ने अपनी 'ग्रे लिस्ट' में रखा है। भारत उसे ब्लैक लिस्ट यानी काली सूची में डालने की मांग कर रहा है।

हिलेरी हारीं, पर नाटक जीता

हिलेरी क्लिंटन के राजनीतिक संघर्ष पर आधारित नाटक अमेरिका में बेहद लोकप्रिय हुआ है।

न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लॉरा कॉलिन्स-ह्यूजेस

चार जुलाई, 2015 को, जो कि सप्ताहांत भी था, जब हिलेरी क्लिंटन डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार के तौर पर अपने चुनाव अभियान में व्यस्त थीं, तब मैसाचुसेट्स के फैलमाउथ में थियेटर के शौकीनों को हिलेरी के जीवन पर लुकास नैथ के नाटक, *हिलेरी ऐंड क्लिंटन* के बारे में जानकारी मिली, जिसे कि अब ब्रॉडवे में दिखाया जाना है। 2008 के प्राइमरीज पर आधारित, जब कि हिलेरी एक करिश्माई शुरुआत के समानांतर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही थीं, इस नाटक में हास्य और त्रासदी, दोनों हैं। राष्ट्रपति चुनाव को केंद्र में रखते हुए यह नाटक बताता है कि औरत होने के अलावा बिल क्लिंटन से शादी के बोझ ने भी पुरुषवर्चस्ववादी राजनीति में हिलेरी क्लिंटन के आगे बढ़ने के रास्ते में किस तरह मुश्किलें खड़ी कीं।

यह नाटक आगामी मार्च में गोल्डन थियेटर में आ रहा है, जिसमें हिलेरी क्लिंटन की भूमिका में लॉरी मैटकाफ और बिल क्लिंटन के किरदार में जॉन लिथगो हैं। गौरतलब है कि अमेरिका के अलग-अलग शहरों में अलग-अलग लोगों ने इस

नाटक का निर्देशन किया है।

यह नाटक अमेरिका के उस सांस्कृतिक परिदृश्य पर है, जिसमें महिलाओं को राजनीति में भी सामाजिक दोहरेपन का सामना करना पड़ता है। इस नाटक के साथ आश्चर्यजनक यह है कि इसे 2008 में लिखा गया, लेकिन वर्ल्ड प्रीमियर के लिए इसे आठ साल तक इंतजार करना पड़ा, जब अप्रैल, 2016 में इसका प्रदर्शन शिकागो के विक्टरी गार्डंस थियेटर में हुआ। चार्ल्स ईशरवुड ने इस नाटक के बारे में द *न्यूयॉर्क टाइम्स* में लिखा कि हिलेरी ने इस नाटक के निर्देशक नैथ को अतिरिक्त रूप से सतर्क पाया। लेकिन क्रिस जोन्स ने द *शिकागो ट्रिब्यून* में लिखते हुए इस नाटक को साहसी, बेहद मनोरंजक और महत्वपूर्ण लेखन बताया। यह नाटक दिखाता है कि सार्वजनिक तौर पर हिलेरी को कितना सख्त होना चाहिए, वह कितनी नरम हो सकती हैं और इन दोनों के बीच ऐसा संतुलन बिठाना क्या संभव है, ताकि वह निंदा की पात्र न बनें।

निर्देशक चे यू ने जब पहली बार यह नाटक 2012 में पढ़ा, तब वह बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने इसे स्त्रीवादी और त्रासद पाया, क्योंकि यह नाटक समाज में स्त्रियों की भूमिका के शाश्वत सवाल से टकराता था। 2014 की गर्मियों में विक्टरी गार्डंस में इसी पर एक नाटक किया, जिसमें वह कला निर्देशक थे। 2015 में वह और नैथ इस नाटक को केप कॉड में ले गए। आज की तरह तब इसे हिलेरी की जीवनी के तौर पर नहीं देखा जा रहा था। चौतरफा घिरीं और राजनीतिक अस्तित्व की जंग में डरी हुई हिलेरी वह नहीं हैं, जैसी कि वास्तविक हिलेरी हैं। ऐसा ही इस नाटक के पुरुष पात्रों के बारे में, चाहे वह बिल क्लिंटन हों या बराक ओबामा, भी कहा जा सकता है।

इसमें वास्तविकता और काल्पनिकता का मिश्रण है। चूंकि हिलेरी के बारे में सभी जानते हैं, ऐसे में, नाटक को इस तरह पेश करने की कोशिश की गई है, ताकि दर्शकों को कुछ तथ्य नए लगें।

इस हफ्ते के शब्द

हिना जायसवाल

फ्लाइट लेफ्टिनेंट हिना जायसवाल ने भारतीय वायु सेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनकर इतिहास रच दिया है।

लिबरलिज्म (LIBERALISM)

रैमंड विलियम्स ने अपनी पुस्तक कीवर्ड्स में बताया है कि लिबरलिज्म शब्द का सबसे ज्यादा उपयोग और दुरुपयोग पाकिस्तान में होता है।

महिलाओं के सेलफोन

80 फीसदी

महिलाओं के पास अपने सेलफोन हैं निम्न व मध्य आय वर्ग देशों में, भारत में यह आंकड़ा 59 फीसदी है, जीएसएमए-2019 की रिपोर्ट।